



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 28 मार्च, 2002/7 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 28 मार्च, 2002

संख्या 1-27/2002-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2002

(2002 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(अजय भण्डारी),

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2002 का विधेयक संख्यांक 8.

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन)
विधेयक, 2002**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971
(1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2002 है। संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ।

(2) यह अगस्त, 2002 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा।

(1971 का 4) 2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 8 का
धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में "चार हजार" शब्दों के स्थान पर संशोधन।
"पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान या उसके स्थान पर निवास स्थान पर स्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय के कारण अधिकतम चार हजार रुपये प्रतिमास की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, अब इस राशि को चार हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 8 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला:

....., 2002.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष 0.24 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या जी० ए० डी०सी० (पी० ए०) (4)-24/94-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2002 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2002.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES
(AMENDMENT) BILL, 2002

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the fifty third year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2002.

Short title
and Com-
mencement,

(2) It shall come into force on the first day of August, 2002.

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, in sub-section (1) in first proviso, for the words "four thousand", the words "five thousand" shall be substituted.

Amend-
ment of
section 8.

(4 of 1971)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Speaker and Deputy Speaker is entitled to reimburse maximum four thousand rupees per month on account of expenditure on local and outside calls in respect of the telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence. Now, it has been decided to amend section 8 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 and to exercise this amount from four thousand rupees to five thousand rupees. This has necessitated the amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 2002.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer, to the tune of Rs. 0.24 lakh per annum. As the proposed amendment is prospective in effect, there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. GAD-C-(PA) (4)-24/94-II]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 2002, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.